राज्य की ओर से उठाई गई दलीलों को स्वीकार किया जाना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई दलीलें खारिज की जा सकती हैं।परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाती है।हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

आर.एन.आर

न्यायमूर्ति ए. बी. एस. गिल और न्यायमूर्ति वी. एस. अग्रवाल, के समक्ष

साधु सिंह और अन्य. याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी. 2000 का नंबर 15941

16 जनवरी, 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226- लेवल 3 पर वरिष्ठ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए त्वरित वरिष्ठता के आधार पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को लेवल 4 (अधीक्षक) तक पदोन्नति देना- सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी कैच-अप के सिद्धांत के आधार पर पहले से पदोन्नत, आरक्षित श्रेणी की तुलना में निचली श्रेणी में अपनी मूल वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर रहे - आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को गलत तरीके से पदोन्नत किया गया, त्वरित, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के आधार पर लेवल 3 पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके ऊपर रखकर अवर

सचिवों के रूप में पदोन्नत किया गया। -तृतीय श्रेणी के स्तर से परे हरियाणा में कोई आरक्षण नीति नहीं - उपाधीक्षक के स्तर पर पकड़ के नियम के आधार पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से वरिष्ठ हो जाते हैं । याचिकाकर्ताओं को उपाधीक्षक के पद पर वापस किया जाए । हालाँकि, अधीक्षक के रूप में उनकी पदोन्नति सुरक्षित रही, क्योंकि वह 1 मार्च, 1996 से पहले की गई थी- रिट खारिज, याचिकाकर्ताओं को अधीक्षक के पद पर वापस करने का आदेश बरकरार रखा गया

अभिनिर्धारित किया कि राज्य ने उपाधीक्षक स्तर तक आवश्यक आरक्षण दिया है। **अजीत सिंह- द्वितीय बनाम पंजाब राज्य, 1999 (7) एस सी सी 209** के मामले में निर्णय के संदर्भ में, 1 मार्च, 1996 तक पदोन्नत किए गए लोग सुरक्षित हैं और कोई आरक्षण नहीं है।कोई आरक्षण नहीं हो सकता है लेकिन आगे कोई पदोन्नति नहीं है कि वे कल्पना के किसी भी विस्तार से सामान्य उम्मीदवारों पर वरिष्ठता का दावा कर सकते हैं।यदि आरक्षण के सिद्धांत की गलत सिद्धांत की गलत धारणा के कारण, कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 1 मार्च, 1996 के बाद पदोन्नत किया गया था, तो उन्हें नीचे गिरना पड़ा और उस पद पर वापस आना पड़ा जिसके बारे में वे संरक्षण चाहते हैं ।ऐसा इसलिए है क्योंकि अजीत सिंह-2 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समीक्षा की अनुमति दी थी और आरक्षण के कारण पदोन्नत लोगों को तदर्थ माना था। नतीजतन, सभी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार जो उप-अधीक्षक के स्तर पर याचिकाकर्ताओं के बराबर होंगे, जहां कोई आरक्षण नहीं है, वे याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ हो जाएंगे। एकमात्र आशा की किरण यह होगी कि याचिकाकर्ताओं को वापस नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वे 1 मार्च, 1996 से पहले अधीक्षक बन गए थे।। याचिकाकर्ता नंबर 1 को त्वरित वरिष्ठता के आधार पर 3 अप्रैल 1991 को अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था, वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवारों के दावे

को नजरअंदाज करते हुए जिन्हें बाद में लेवल 3 पर पदोन्नत किया गया था। स्तर 4 पर, याचिकाकर्ता की वरिष्ठता की समीक्षा की गई थी और जब सामान्य उम्मीदवार स्तर 4 पर पहुंचे तो उसे फिर से तय किया गया था।उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, उन्हें अधीक्षक के पद से वापस नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन्हें 1 मार्च, 1996 से पहले पदोन्नत किया गया था।याचिकाकर्ता संख्या 2 की भी यही स्थिति है।नतीजतन, हम याचिकाकर्ताओं को अधीक्षक के पद पर वापस करने के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

(पैरा 30 &31)

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता और

एच. एस. गिल, वरिष्ठ अधिवक्ता,

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरि चंद।

सूर्यकांत, महाधिवक्ता, हरियाणा नरेंदर हुड्डा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा के साथ, राज्य के लिए

आर. के. मलिक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 13,23,26,27,30,47,48,53,62 और 77 के लिए।

पी. एस. पटवालिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण 24,25,29 और 78 के लिए ।

प्रत्यर्थी संख्या 14 की ओर से अधिवक्ता पुनीत कंसल के साथ अधिवक्ता राजीव आत्मा राम।

के. एल. सुनेजा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 55 और 56 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति वी. एस. अग्रवाल,

(1) इस सामान्य निर्णय द्वारा, हम 2000 की नागरिक याचिका संख्या 7696 और 15941 के कुल निपटान का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि इन दोनों रिट याचिकाओं में शामिल कानून और तथ्यों के प्रश्न समान हैं।

(2) साधु सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य शीर्षक वाली 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 15941 से संयोजित तथ्य यह हैं कि साधु सिंह याचिकाकर्ता को 9 अगस्त, 1971 को क्लर्क के रूप में भर्ती किया गया था।उन्हें 2 मई, 1977 को सहायक और 21 मार्च, 1990 को उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था।याचिकाकर्ता नंबर 2, बी. एल. ग्रोवर को 12 अगस्त, 1971 को क्लर्क के रूप में भर्ती किया गया था।उन्हें 28 जुलाई, 1977 को सहायक के रूप में और 23 नवंबर, 1990 को उप अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था।हरियाणा राज्य में, उपाधीक्षक के स्तर तक, जो कि एक श्रेणी-तीन का पद है, आरक्षण की नीति है, उससे आगे की नहीं।दोनों याचिकाकर्ताओं को क्रमशः 3 अप्रैल, 1991 और 8 जुलाई, 1991 को अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

(3) यह दावा किया जाता है कि **भारत संघ बनाम वीर पाल सिंह चौहान**[1] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, **अजीत सिंह-2 बनाम पंजाब राज्य**[2] और **सुबे सिंह बहमनी बनाम हरियाणा राज्य**[3] के मामले में उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णय के बाद, (3) प्रतिवादी राज्य ने वरिष्ठता सूची तैयार की थी।याचिकाकर्ता के अनुसार, वे उत्तरदाता संख्या 2 से 10 को छोड़कर सभी प्रतिवादीगण से वरिष्ठ हैं जो पकड़ नियम

[1] 1995 (6) एस सी सी 684

[2] 1999 (7) एस सी सी 209

[3] 1999 (8) एस सी सी 213

के आधार पर वरिष्ठ हो गए हैं।अन्यथा इस प्रकार तैयार की गई वरिष्ठता सूची को उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत कहा गया है।याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि हरियाणा राज्य द्वारा 17 मई, 2000 की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें सभी प्रतिवादीगण यानी उत्तरदाता संख्या 2 से 78 को वरिष्ठता दी गई है, जो उच्चतम न्यायालय के फैसलों के विपरीत है क्योंकि उत्तरदाता संख्या 11 से 78 उप अधीक्षक के स्तर तक नहीं पहुंचे थे जब याचिकाकर्ताओं को हरियाणा राज्य में अधीक्षक और उसके बाद अवर सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था।यह उल्लेख किया गया है कि हरियाणा राज्य ने ए. सी. कपिल, प्रतिवादी संख्या 13 और बी. आर. चावला, प्रतिवादी संख्या 14 के अलावा धानी राम, प्रतिवादी संख्या 23 को पदोन्नत किया है, जो अन्यथा याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ थे।जब याचिकाकर्ता संख्या 1 को 3 अप्रैल, 1991 को अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था, तब उन्हें उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था।इसी तरह, यह बताया गया है कि सोम प्रकाश शर्मा, प्रतिवादी संख्या 26 और एस. एन. चुघ, प्रतिवादी संख्या 27, याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ थे और जब तक याचिकाकर्ता संख्या 2 ने अधीक्षक के रूप में पदभार संभाला था, तब तक उन्हें उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था।चित्रण के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 1 का संबंध है, कैच-अप नियम के सिद्धांत के अनुसार, केवल प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 यानी सोमा देवी को आर. डी. गुप्ता के रूप में उल्लिखित व्यक्ति ही पकड़ेंगे। जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 1 की वरिष्ठता का संबंध है, यह निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया हैः–

क्रम संख्या	डिप्टी के रूप में पदोन्नति की	अधीक्षक (द्वितीय	वरिष्ठता सूची में एस. आई. नं.

1.	साधु सिंह (प्रतिवादी...)	21-3-1990	3-4-1991	312
2.	आर डी गुप्ता	30-4-1990	3-4-	313
3.	के एल शर्मा	8-10-1990-,	3-4-	314
4.	धरम पाल	23-11-1990	3-4-	315
5.	एम. एल. घड़	23-11-1990	3-4-	316
6.	एस. एन. बत्रा	23-11-1990	8-7-	317
7.	एच. सी. छाबड़ा	7-1-1991	8-7-	319
8.	के. एल. भंड्ला	7-1-1991	29-7-	320
9.	आतम लाल	7-1-1991	29-7-	321
10.	एच. सी. हूड्डा	7-1-1991	29-7-	322
11.	ओ. पी. शर्मा	22-2-1991	29-7-	325
12.	सोमा देवी सहगल	22-3-1991	29-7-	326

(4) जहां तक प्रतिवादी नंबर 2 का सवाल है, केवल बीआर चावला तक उल्लेखित व्यक्ति ही कैच अप करेंगे ।उन्होंने निम्नानुसार प्रदर्शित

क्रम संख्या		डिप्टी के रूप में पदोन्नति की तिथि	अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी) के	वरिष्ठता सूची में एस. आई. नं.
13.	बी. एल. ग्रोवर (एस/सी याचिकाकर्ता संख्या 2)	23-11-1990	8-7-1991	318
14.	एच. सी. छाबड़ा	7-1-1991	8-7-	319

सीनियर नाम नं.	डिप्टी के रूप में पदोन्नति की तिथि।	एस. आई. की तिथि। नं. इन वरिष्ठता सूची को अधीक्षक के रूप में बढ़ावा दें	
15. के. एल. भंडुला	7-1-1991	29-7-1991	320
16. आतम लाल	7-1-1991	29-7-1991	321
17. एच. सी. हुड्डा	7-1-1991	29-7-1991	322
18. ओ. पी. शर्मा	22-2-1991	29-7-1991	325
19. सोमा देवी ______	22-3-1991	29-7-1991	326
20. बावा सिंह	22-4-1991	18-9-1991	327
21. लेहना सिंह	22-4-1991	18-9-1991	328
22. के. एस. गुलेरिया	22-4-1991	18-9-1991	329
23. आर. डी. एस.	24-4-1991	18-9-1991	330
24. ए. सी. कपिल	22-4-1991	18-9-1991	331
25. बी. आर. चावला	22-4-1991	24-10-1991	332

(5) इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 6 अक्टूबर, 2000 को आदेश पारित किया था, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को ऊपर उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आधार पर अधीक्षक के पद पर वापस भेज दिया गया है।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वास्तव में, यह फैसले का गलत अध्ययन है और वे अन्य निजी प्रतिवादीगण से वरिष्ठ हैं और वर्तमान रिट याचिका में आदेश पर सवाल उठाया जा रहा है।

(6) सम्मत सिंह और अन्य लोगों द्वारा दायर संबंधित रिट याचिका में भी इसी तरह के सवाल उठाए गए हैं।इस प्रकार तैयार की गई वरिष्ठता सूची, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पर हमला किया जा रहा है।

(7) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों रिट याचिकाओं को चुनौती दी जा रही है।सभी प्रतिवादीगण ने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं के तर्क में कोई दम नहीं है।वे दावा करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार, साधु सिंह और एक अन्य द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 14 तक दायर रिट याचिका याचिकाकर्ताओं पर वरिष्ठता हासिल करेगी, लेकिन यह सही नहीं है।यह दावा किया जाता है कि जब याचिकाकर्ता संख्या 1 साधु सिंह को 4 मार्च, 1991 को अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 2 बी. एल. ग्रोवर को 8 जुलाई, 1991 को अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था।इसके बाद, कई अन्य प्रतिवादीगण, जो सामान्य उम्मीदवार थे, कैच-अप नियम के सिद्धांत के आधार पर वरिष्ठ हो गए थे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार स्तर-4 (अधीक्षक) तक चले गए थे, स्तर-3 पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार की वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए, स्तर-4 पर वरिष्ठता को इस आधार पर फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए कि पदोन्नति के लिए आरक्षित उम्मीदवार का समय कब आया होगा।प्रत्यर्थी-राज्य ने दावा किया है कि उसने अजीत सिंह-2 (उपरोक्त) के मामले में उल्लिखित नियम का सख्ती से पालन किया था।यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को त्वरित पदोन्नति के माध्यम से सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था।. उन्होंने सामान्य वर्ग के 13 वरिष्ठ नागरिकों को पछाड़ा। इसके बाद, उन्हें त्वरित पदोन्नति के माध्यम से उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया।उन्होंने 158 से अधिक सामान्य उम्मीदवारों को पार किया जो स्तर-2 पर उनसे वरिष्ठ थे।स्तर-4 यानी अधीक्षक में कोई आरक्षण नहीं है।स्तर-4 में पदोन्नति स्तर-3 में वरिष्ठता का परिणाम है।उक्त निर्णय के संदर्भ में, स्तर-3 पर साधु सिंह याचिकाकर्ता की वरिष्ठता की समीक्षा की गई थी और स्तर-3 पर पहुंचने पर बार-बार सामान्य उम्मीदवारों को उनके ऊपर रखा गया था।साधु सिंह याचिकाकर्ता को 3 अप्रैल, 1991 को त्वरित वरिष्ठता के आधार पर अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था,

सामान्य उम्मीदवारों के दावे को नजरअंदाज करते हुए जिन्हें पदोन्नत किया जाता अगर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार के मामले को स्तर-3 पर माना जाता।स्तर-4 पर, साधु सिंह याचिकाकर्ता की वरिष्ठता की समीक्षा की जानी थी और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून के संदर्भ में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के स्तर-4 पर पहुंचने पर उसे फिर से निर्धारित किया जाना था।1 मार्च, 1996 से पहले की गई पदोन्नति को संरक्षित किया जाना था, लेकिन वरिष्ठता को फिर से निर्धारित किया जाना था।चूंकि साधु सिंह याचिकाकर्ता को 3 अप्रैल, 1991 को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, इसलिए उस पदोन्नति की रक्षा की जा रही है।इसी तरह, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 अपनी वरिष्ठता खो देगा, हालांकि अधीक्षक के रूप में उनकी पदोन्नति को संरक्षित किया जा रहा है।

(8) यह भी इंगित किया गया है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर पदोन्नति संख्या 1 को गलत तरीके से लागू करने और त्वरित वरिष्ठता के कारण आरक्षण कोटे से अधिक किया गया था।इसलिए, उन्हें गलती से 19 फरवरी, 1997 को अवर सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था, यानी 1 मार्च, 1996 के बाद, और इसलिए, उन्हें वापस किया जा सकता है।याचिकाकर्ता संख्या 2 की भी यही स्थिति थी चूंकि उन दोनों को 1 मार्च, 1996 से पहले पदोन्नत किया गया था, इसलिए डिप्टी अधीक्षक के पद पर वापस नहीं किया जा रहा था ।नतीजतन, याचिकाकर्ताओं के दावों का खंडन किया गया है।

(9) दलीलों के दौरान, यह बताया गया कि याचिकाकर्ता साधु सिंह और एक अन्य ने पहले एक रिट याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था और इसलिए, वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है।दलीलों के दौरान, यह पता चला कि उस समय तक दोनों याचिकाकर्ताओं को वापस करने का विवादित आदेश पारित नहीं किया गया था।अनिवार्य रूप से, यह समय से पहले था। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि वर्तमान रिट याचिका रेस ज्यूडिकाटा या यहां तक कि रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के

सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं है।

(10) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने विवादित आदेश को चुनौती देने के अलावा तर्क दिया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है।उन्होंने आग्रह किया कि कारण बताओ नोटिस दोषपूर्ण था और दूसरी बात, कोई उचित सुनवाई भी नहीं की गई थी।

(11) इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत सभी सभ्य देशों में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं और हमारे न्यायशास्त्र में तो और भी अधिक मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि, जब भी ऐसा कोई सवाल उठता है, तो इसकी कसौटी पर परख की जानी चाहिए।यदि कोई पक्षपात पैदा हुआ है, तो जाहिर है, आदेश को बनाए नहीं रखा जा सका।लेकिन केवल अगर कारणदर्शक नोटिस में थोड़ा दोष है, लेकिन संबंधित व्यक्ति विवाद के स्वरूप के बारे में पूरी तरह से जागरूक था और वह यह जानते हुए इसका विरोध करता है कि उसे किस विवाद का मुकाबला करना है, तो यह कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है।

(12) इसमें, वास्तव में, एक कारणदर्शक नोटिस दिया गया था और उसी का विरोध किया गया था।यह नहीं दिखाया गया है कि क्या पक्षपात, यदि कोई हो, पैदा हुआ था।यह दिखाए जाने के अभाव में कि याचिकाकर्ता कैसे अपना बचाव ठीक से नहीं कर सके, हम यह मानने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि कारण दर्शाएँ नोटिस ने पक्षपात पैदा किया था और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।अन्यथा भी, बहस के दौरान, जो कुछ भी आग्रह किया जाना था, हमारे सामने बहस की गई थी।दलीलों को लंबे समय तक सुना गया।विवाद वही था जो उस समय उठाया जाना था।इसलिए, हम उन्हें किसी भी स्थिति में अधिकारियों को वापस भेजना अनावश्यक समझते हैं।दोनों कोणों से देखते हुए,

विद्वान वकील द्वारा इस तरह से सोचे गए उक्त तर्क का कोई लाभ नहीं है।

(13) वर्तमान मामले में मुख्य विवाद की ओर लौटते हुए, हम यह कहना आवश्यक समझते हैं कि हमारा कार्य आसान हो गया है क्योंकि हम मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय की घोषणाओं से संबंधित हैं।। **<u>आर. के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य</u>**[4], वीर पाल चौहान का मामला (ऊपर), अजीत सिंह-2 का मामला (ऊपर) और **<u>सबस सिंह बहमनी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य</u>**[5] के मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसलों के आलोक में दोनों ओर से प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए।इस स्तर पर हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि हमें केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या वरिष्ठता सूची और विचाराधीन आदेश उपरोक्त घोषणा में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पारित किए गए हैं या नहीं।चूंकि विवादग्रस्त मामले पर उच्चतम न्यायालय पहले ही निर्णय दे चुका है, इसलिए हम इसके उचित कार्यान्वयन को देखने के अलावा और कुछ नहीं कह सकते।

(14) अनुलग्नक पी.-4 हरियाणा सरकार द्वारा पारित आदेश है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता साधु सिंह और बी. एल. ग्रोवर दोनों को अधीक्षक के पद पर वापस भेज दिया गया है। अनुलग्नक पी-4 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः–

> “2. निर्णय के अनुसरण में, सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में त्वरित वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति की समीक्षा की गई, फिर से तय की गई, और पदोन्नति की तारीखों का आकलन किया गया और अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच प्रसारित किया गया विसंगतियाँ, यदि कोई हों, दस दिनों के भीतर इंगित करने के

[4] 1995 (2) आर.एस.जे. 895

[5] 1994 (4) आर.एस.जे. 171

लिए ।अधिकारियों/अधिकारियों द्वारा बताई गई विसंगतियों पर विचार करने के बाद, जो लिपिक प्रकृति की थीं और जिनमें कोई कानूनी बिंदु शामिल नहीं था, मानित तिथियों को letter No. 22/7/97-Estt-I, दिनांक 30th June, 2000.के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया था।

(3) श्री साधु सिंह, बी. एल. ग्रोवर, भरत सिंह, तारा चंद, पूरन मल, सुमेर चंद और सुबे सिंह, जिन्हें त्वरित वरिष्ठता के आधार पर 1 मार्च, 1996 के बाद अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया था, को अधीक्षक के पद पर वापस भेजा जा सकता है, जो वे 1 मार्च, 1996 को धारण कर रहे थे।इसलिए, इन अधिकारियों को 21 जून, 2000 के ज्ञापन संख्या 14/4/99-Est-I के माध्यम से कारण दर्शाएँ नोटिस दिए गए थे कि उन्हें अधीक्षक के पद पर क्यों नहीं वापस किया जाना चाहिए।उक्त कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने से पहले ही इन अवर सचिवों को एक समिति द्वारा सुना गया था और इन अवर सचिवों द्वारा की गई दलीलों पर समिति द्वारा गहन विचार किया गया था और उनकी प्रस्तुतियाँ योग्यता से रहित होने के कारण, यह महसूस किया गया कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार वापस किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और उन पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

4. उपरोक्त अवर सचिवों के कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार किया गया है।उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के बाद और संशोधित वरिष्ठता, पदोन्नति की मानित तिथियों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए, सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन अवर सचिवों द्वारा की गई दलीलों में कोई सार नहीं है और वे अधीक्षक के पद पर वापस आने के लिए उत्तरदायी हैं।

5. इसके आधार पर, हरियाणा के गवर्नर ने खुशी खुशी कुछ निम्नलिखित अंडर सचिवों को तुरंत प्रभाव से पदाधिकारियों के पद पर वापस बुला दिया है, जिनका वेतनमान है Rs. 6500–10,500 और अतिरिक्त विशेष वेतन Rs. 200 के साथ।

1. श्री साधु सिंह
2. श्री बी. एल. ग्रोवर
3. श्री भरत सिंह
4. श्री तारा चंद
5. श्री पूरन माई
6. श्री सुमेर चंद
7. श्री सुबक सिंह

6. उन्हें प्रतिष्ठान-1 शाखा में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।"

(15) इसी तरह, संबंधित रिट याचिका में, विवादित वरिष्ठता सूची संलग्न की गई थी और समान आधारों पर आलोचना की जा रही है। आर. के. सभरवाल और अन्य मामलों (उपर्युक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

".. इसलिए, अवसर की समानता सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणी को रोस्टर को तब तक संचालित करने की अनुमति देनी है जब तक कि संबंधित नियुक्तियां/पदोन्नति रोस्टर में उनके लिए निर्धारित पदों पर कब्जा नहीं कर लेती हैं।रोस्टर और "चालू खाते" का संचालन इसके बाद समाप्त होना चाहिए।प्रारंभिक पदों को भरने के बाद संवर्ग में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(16) हालाँकि, दी गई व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि रोस्टर के काम करने के बारे में व्याख्या दी गई थी जो केवल

भविष्यलक्षी प्रभाव से काम करती है।आर. के. सभरवाल के मामले (ऊपर) के निर्णय से निष्कर्ष स्पष्ट हैं।अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण रिक्तियों के बजाय पदों के लिए है। "पदों" और "रिक्तियों" के बीच का अंतर निकाला गया था और यह माना गया था कि रिक्तियों को होने में सक्षम बनाने के लिए एक पद "अस्तित्व में" होना चाहिए। संवर्ग-शक्ति को संवर्ग में शामिल पदों की संख्या से मापा जाना चाहिए।इस प्रकार, पहले की सोच को मंजूरी नहीं दी गई थी और यह माना गया था कि उक्त कार्यान्वयन कि आरक्षण पद के अनुसार होना चाहिए, केवल संभावित रूप से तैयार किया जाएगा।

(17) इसके बाद **<u>भारत संघ और अन्य बनाम विरपाल सिंह चौहान और अन्य</u>**[6] के मामले में निर्णय लिया गया।पहली बार वरिष्ठता बनाम सामान्य उम्मीदवारों और आरक्षित उम्मीदवारों से संबंधित विवाद का निपटारा किया गया।जिस सिद्धांत का अब वर्णन किया जा रहा है, उसका उल्लेख किया गया है। हमें फिलहाल वीरपाल सिंह चौहान के मामले के तथ्यों से कोई सरोकार नहीं है ।हम मूल रूप से उन सिद्धांतों से संबंधित हैं जो निर्धारित किए गए थे।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था

> " टाइल पदोन्नत श्रेणी में वरिष्ठता की स्थिति के रूप में आरक्षित उम्मीदवारों और सामान्य उम्मीदवारों के बीच किसी भी समय ग्रेड 'सी' में उनकी अंतर वरिष्ठता स्थिति के समान होगी बशर्ते कि उस समय, सामान्य उम्मीदवार और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार दोनों एक ही ग्रेड में हों।यह नियम संचालित करता है कि क्या सामान्य उम्मीदवार पदोन्नति के उसी

---

[6] 1996 (I) R.S.rJ. d()f)

बैच में शामिल है या बाद के बैच में।(यही कारण है कि उपरोक्त परिपत्र/पत्र इस तरह के किसी भी अंतर को नहीं बनाते हैं या मान्यता नहीं देते हैं।) दूसरे शब्दों में, भले ही किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को उसके वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार की तुलना में आरक्षण/रोस्टर के नियम के आधार पर पहले पदोन्नत किया जाता है और वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार को बाद में उक्त उच्च श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है, सामान्य उम्मीदवार ऐसी पूर्व पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर अपनी वरिष्ठता फिर से प्राप्त करता है।ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को पहले की गई पदोन्नति उसे सामान्य उम्मीदवार पर वरिष्ठता प्रदान नहीं करती है, भले ही सामान्य उम्मीदवार को बाद में उस श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है।"

(18) मोटे तौर पर, सिद्धांत यह था कि यदि त्वरित पदोन्नति के माध्यम से, जहां पद के लिए आरक्षण है, एक आरक्षित उम्मीदवार को पदोन्नत किया जाता है, तो यह मूल पद में उनकी अंतर वरिष्ठता को बाधित नहीं करता है।यदि बाद में, एक सामान्य उम्मीदवार को भी उसी पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो वह अपनी मूल वरिष्ठता हासिल कर लेता है।तथापि, **अजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[7], जिसे अजीत सिंह-2 के नाम से जाना जाता है, मामले में संविधान पीठ उक्त विवाद से संबंधित थी।उच्चतम न्यायालय ने विचार के लिए निम्नलिखित चार बिंदु तैयार किएः—

"(1).क्या रोस्टर प्वाइंट पदोन्नत (आरक्षित श्रेणी) अपने निरंतर कार्यकाल की

[7] जे.टी. 1999 (7) एस.सी. 153

तारीख से पदोन्नत श्रेणी में अपनी वरिष्ठता को सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में गिन सकते हैं जो निचली श्रेणी में उनसे वरिष्ठ थे और जिन्हें बाद में उसी स्तर पर पदोन्नत किया गया था?

(2) क्या विरपाल, अजीत सिंह का निर्णय सही है और क्या जगदीश लाल का निर्णय सही है?

(3) क्या सामान्य उम्मीदवारों द्वारा प्रतिपादित 'कैच-अप' सिद्धांत मान्य हैं?

(4) सभरवाल के 'संभावित' संचालन का क्या अर्थ है और अजीत सिंह किस हद तक संभावित हो सकते हैं?

(20) उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ बनाम विरपाल सिंह**[8] में दिए गए निर्णय और **अजीत सिंह जंजुआ बनाम पंजाब राज्य**[9] मामले में पहले के निर्णय को मंजूरी दी। लेकिन **जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य**[10] को अस्वीकार कर दिया।दूसरे शब्दों में, अजीत सिंह-2 के मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय द्वारा पकड़ के नियम को मंजूरी दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिकारों का उचित संतुलन होना चाहिए और यह निष्कर्ष निकाला कि सामान्य उम्मीदवार जो सहायक (स्तर 2) में वरिष्ठ हैं और जो आरक्षित उम्मीदवार के स्तर 4 (अधीक्षक ग्रेड-I) में जाने से पहले अधीक्षक ग्रेड II (स्तर 3) तक पहुंच गए थे, उन्हें स्तर 3 पर वरिष्ठ माना जाएगा।यह उस आधार पर है कि स्तर 4 में पदोन्नति की जानी चाहिए, पहले स्तर 3 पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। बिंदु 1 और 2 का निर्णय करते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

"इसलिए, हम मानते हैं कि रोस्टर पॉइंट पदोन्नत (आरक्षित श्रेणी) (7) जे.टी. में उनकी

[8] जे.टी. 1995 (7) एस.सी. 231
[9] जे.टी. 1996 (2) एस.सी. 727
[10] जे.टी. 1997 (5) एस.सी. 387

निरंतर पदस्थापना की तारीख से पदोन्नत श्रेणी में उनकी वरिष्ठता की गणना नहीं की जा सकती है। 1999 (7) एस.सी. 153 (8) जे.टी. 1995 (7) एस.सी. 231 (9) जे.टी. 1996 (2) एस.सी. 727 (10) जे.टी. 1997 (5) एस.सी. 387 पदोन्नत पद, सामान्य अभ्यर्थी की तुलना में जो निचली श्रेणी में उनसे वरिष्ठ थे और जिन्हें बाद में पदोन्नत किया गया था।।दूसरी ओर, निचले स्तर पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार, यदि वह बाद में पदोन्नति स्तर पर पहुंच जाता है, लेकिन आरक्षित उम्मीदवार की आगे की पदोन्नति से पहले, उसे पदोन्नति स्तर पर, आरक्षित उम्मीदवार के लिए वरिष्ठ माना जाएगा, भले ही आरक्षित उम्मीदवार को पहले उस स्तर पर पदोन्नत किया गया हो।

(21) लेकिन यह माना गया कि यदि कोई आरक्षित उम्मीदवार स्तर 3 पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए स्तर 4 तक जाता है, तो स्तर 4 पर वरिष्ठता को फिर से तय करना होगा जब वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार को स्तर 4 पर पदोन्नत किया जाता है।उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः–

> “......ऐसे मामलों में जहां आरक्षित उम्मीदवार स्तर 3 पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार की वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए स्तर 4 तक चला गया है, स्तर 4 पर वरिष्ठता को फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए (जब वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार को स्तर 4 पर पदोन्नत किया जाता है) इस आधार पर कि स्तर 4 पर पदोन्नति के लिए आरक्षित उम्मीदवार का समय कब आया होता, अगर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवारों के मामले पर उचित समय पर स्तर 3 पर विचार किया जाता।उपरोक्त सीमा तक, हम सामान्य उम्मीदवारों के लिए विद्वान वकील के तर्क के पहले भाग को स्वीकार करते हैं।हमारे विचार में ऐसी प्रक्रिया आरक्षित उम्मीदवारों के अधिकारों और सामान्य उम्मीदवारों

को अनुच्छेद 16 (1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को उचित रूप से संतुलित करेगी।"

(22) इस संबंध में, निम्नलिखित प्रासंगिक निष्कर्ष निकाले गए:-

.." हमारे विचार में, जबकि न्यायालय अतीत की अवैधता से उत्पन्न तत्काल कठिनाई को दूर कर सकते हैं, न्यायालय वरिष्ठता जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान नहीं कर सकते हैं जिनमें तत्काल कठिनाई का कोई तत्व नहीं है।इस प्रकार, जबकि 10 फरवरी, 1995 से पहले किए गए रोस्टर से अधिक पदोन्नति सुरक्षित हैं, ऐसे पदोन्नति प्राप्त व्यक्ति वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं।ऐसे अतिरिक्त रोस्टर प्वाइंट पदोन्नतियों के पदोन्नति संवर्ग में वरिष्ठता की समीक्षा 10 फरवरी, 1995 के बाद करनी होगी और केवल उस तारीख से गणना की जाएगी जिस दिन उन्हें अन्यथा आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा पहले से रखे गए पद पर उत्पन्न होने वाली किसी भी भविष्य की रिक्ति में सामान्य पदोन्नति मिल जाती। "

(23) जहां तक बिंदु 3 और 4 का संबंध है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

"हमने बिंदु 1 और 2 से निपटने के दौरान स्वीकार किया है कि आरक्षित उम्मीदवार जो दो स्तरों पर रोस्टर अंकों (जैसे) द्वारा स्तर 1 से स्तर 2 और स्तर 2 से स्तर 3 तक पदोन्नत होते हैं, वे वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में स्तर 3 पर अपनी वरिष्ठता नहीं गिन सकते हैं, जो आरक्षित उम्मीदवारों के स्तर 4 तक जाने से पहले स्तर 3 तक पहुंच गए थे।सामान्य उम्मीदवार को स्तर 3 पर वरिष्ठ माना जाना चाहिए।

जहां, 1 मार्च, 1996 से पहले, यानी अजीत सिंह के फैसले की तारीख से

पहले, स्तर 3 पर, आरक्षित उम्मीदवार थे जो पहले वहां पहुंचे थे और वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार भी जो बाद में वहां पहुंचे थे, (लेकिन आरक्षित उम्मीदवार को स्तर 4 पर पदोन्नत किए जाने से पहले) और जब इस तथ्य के बावजूद कि वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार को स्तर 3 पर वरिष्ठ माना जाना था (अजीत सिंह को देखते हुए), आरक्षित उम्मीदवार को स्तर 4 पर और पदोन्नत किया जाता है-इस तथ्य पर विचार किए बिना कि वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार भी स्तर 3 पर उपलब्ध था-तो, 1 मार्च, 1996 के बाद, आरक्षित उम्मीदवार की स्तर 4 पर पदोन्नति की समीक्षा करना और उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है (1 मार्च से पहले स्तर 4 पर पहुंचने वाले आरक्षित उम्मीदवार को वापस लिए बिना)।जैसे-जैसे वरिष्ठ आरक्षित उम्मीदवार को बाद में स्तर 4 में पदोन्नत किया जाता है, स्तर 4 पर वरिष्ठता को भी इस आधार पर फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए कि स्तर 3 पर आरक्षित उम्मीदवार को उनकी सामान्य पदोन्नति कब मिली होगी, उन्हें स्तर 3 पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार से कनिष्ठ माना जाता **है।चंदर पॉल बनाम हरियाणा राज्य (**1997 (10) एस सी सी 474) को ऊपर बताए गए तरीके से समझना था।"

(24) हालांकि हम ने उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्षों को विस्तार से दोहराया है, लेकिन कुछ शब्दों में वे हैं कि (i) आरक्षित उम्मीदवार पदोन्नत पद पर अपने निरंतर कार्यकाल की तारीख से पदोन्नत श्रेणी में अपनी वरिष्ठता को उन सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में नहीं गिन सकते हैं जो निचली श्रेणी में उनसे वरिष्ठ थे और जि कि एक बार जब स्तर 3 से परे कोई आरक्षण नहीं है, दूसरे शब्दों में जब अधीक्षक के पद के लिए कोई आरक्षण नहीं है, तो पदोन्नति स्तर 3 पर संशोधित वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए। (iii) ऐसे अतिरिक्त रोस्टर प्वाइंट पदोन्नति के प्रचार संवर्ग

में वरिष्ठता की समीक्षा 10 फरवरी, 1995 के बाद यानी आर. के. सभरवाल के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के बाद की जानी चाहिए।इसे केवल उस तारीख से गिना जाएगा जिस दिन उन्हें भविष्य की किसी भी रिक्ति में सामान्य पदोन्नति मिलती, (iv) यदि किसी आरक्षित उम्मीदवार को, गलत पदोन्नति पर भी, स्तर 4 में पदोन्नत किया गया है, तो उसे वापस नहीं किया जाएगा, (v) जब वरिष्ठ आरक्षित उम्मीदवार को बाद में स्तर 4 में पदोन्नत किया जाता है, तो स्तर 4 पर वरिष्ठता को फिर से तय करना पड़ता है।दूसरे शब्दों में, वरिष्ठता को फिर से खींचा जाना चाहिए जब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार आरक्षित उम्मीदवार को उस स्तर तक पकड़ते हैं जहां आरक्षण निर्धारित किया गया है।यदि वह पहले के स्तर पर आरक्षित उम्मीदवार से वरिष्ठ थे, तो उन्हें फिर से वरिष्ठ माना जाएगा, भले ही उन्हें बाद में पदोन्नत किया जा सके। उसी तारीख को, याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों, जिन्हें **सुबे सिंह बहमनी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य**[11] के रूप में जाना जाता है, के हरियाणा अधिकारी का मामला सुना गया।यह विशेष रूप से नोट किया गया कि हरियाणा में उप अधीक्षक के स्तर से परे कोई आरक्षण नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।उपरोक्त उल्लिखित सिद्धांतों को दोहराया गया और फैसले के पैराग्राफ 19 और 20 में उच्चतम न्यायालय ने साधु सिंह और बी. एल. ग्रोवर याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करते हुए कहाः–

[11] जे.टी. 1999 (7) एस.सी. 53

19. हालाँकि, जहाँ तक आरक्षित उम्मीदवारों साधु सिंह और बी. एल. ग्रोवर का संबंध है, जब तक उन्हें 3 अप्रैल, 1991 और 8 जुलाई, 1991 को अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया, तब तक सभी 4 रिट याचिकाकर्ता डिप्टी कलेक्टर बन गए। अधीक्षक सम्मत सिंह समान स्थिति में प्रतीत होते हैं।रिट याचिकाकर्ता 1 से 4 6 मई, 1985,30 अप्रैल, 1990 और 7 जनवरी, 1991 को डिप्टी अधीक्षक के स्तर तक पहुँच गए। इसलिए, चार रिट याचिकाकर्ताओं ने डिप्टी अधीक्षक के स्तर पर साधु सिंह, बी. एल. ग्रोवर और सम्मत सिंह पर वरिष्ठता का सही दावा किया है। उस स्थिति में, भले ही उपरोक्त आरक्षित उम्मीदवारों को पहले डिप्टी अधीक्षकों के रूप में पदोन्नत किया गया हो , उन्हें उस स्तर पर 4 रिट याचिकाकर्ताओं के कनिष्ठ के रूप में माना जाना चाहिए।यह सच है कि 1 मार्च, 1996 से पहले की गई पदोन्नति, जब अजीत सिंह नंबर 1 का निर्णय लिया गया था, कायम रहेगी और कोई वापसी नहीं होगी।लेकिन वरिष्ठता उपर बताए अनुसार डिप्टी अधीक्षक स्तर पर सामान्य उम्मीदवारों को तय किया जाना है।

(25) यदि इन चार सामान्य उम्मीदवारों की वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा गया है जब आरक्षित उम्मीदवारों को अधीक्षक और उससे ऊपर के रूप में पदोन्नत किया गया था, तो इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।इसलिए, 4 रिट याचिकाकर्ताओं (सामान्य वर्ग के उम्मीदवार) और साधु सिंह, बी. एल. ग्रोवर और सम्मत सिंह के बीच अधीक्षक और अवर सचिव के स्तर पर पदोन्नति और वरिष्ठता की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि उनका मामला ज्ञान सिंह के मामले जैसा नहीं है।अजीत सिंह नं. II को लागू करना होगा।अंक 1 से 3, जैसा कि वहां तय किया गया है, वरिष्ठता को नियंत्रित करेगा और अंक 4, सभरवाल और अजीत सिंह नंबर 1 की संभावना को नियंत्रित करेगा।संबंधित कट ऑफ तिथियों का पालन करना होगा।इस अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।”

---

(11) जे.टी. 1999 (7) एस.सी. 53

(26) प्रतिवादीगण की ओर से, यह आग्रह किया गया कि सुबे सिंह बहमनी के मामले (उपरोक्त) में यह विशेष रूप से नोट किया गया था कि साधु सिंह और बी. एल. ग्रोवर कुछ अन्य व्यक्तियों से जूनियर होंगे और यह अंतर-पक्षीय निर्णय था और अब कुछ अन्य व्यक्ति जिन्हें प्रतिद्वंद्वी कहा जाता है, वे प्रतिवादीगण पर चढ़ाई नहीं कर सकते।

(27) यह माना जाना चाहिए कि अजीत सिंह-2 और सुबे सिंह बहमनी के मामले में फैसले को एक साथ पढ़ा जाए और एक को दूसरे से अलग नहीं पढ़ा जा सकता है।हम पहले ही देख चुके हैं कि अजीत सिंह-2 (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब कोई आरक्षित उम्मीदवार स्तर 3 पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए स्तर 4 तक चला जाता है, तो स्तर 4 पर वरिष्ठता को फिर से तय करना पड़ता है।दूसरे शब्दों में, इसके विपरीत सामान्य उम्मीदवारों के तर्क को खारिज कर दिया गया था।सुबे सिंह बहमनी के मामले (ऊपर) में, अंक 1 से 3 पर निर्णय को नहीं छुआ गया था।उन्हें स्वीकार कर लिया गया।इसलिए, जैसा कि दावा किया जा रहा है, कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

(28) सुबे सिंह बहमनी के मामले (ऊपर) में, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता अन्य लोगों की तुलना में उपाधीक्षक के स्तर पर वरिष्ठ थे जो प्रतिवादीगण का मुकाबला कर रहे है इसका मतलब यह नहीं होगा कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पकड़ नियम को समाप्त कर दिया गया था ।इसका कारण यह था कि सर्वोच्च न्यायालय केवल उपाधीक्षक स्तर तक की वरिष्ठता का निर्णय कर रहा था।यह एक ऐसा पद है जहाँ तक आरक्षण की अनुमति थी।जब स्तर 4 यानी अधीक्षक के पद पर, कोई आरक्षण नहीं है, जाहिर है, कोई भी पदोन्नति वरिष्ठता

के सिद्धांत की अनदेखी करते हुए की गई है।यह रोस्टर बिंदु से अधिक होगा क्योंकि उस स्तर पर कोई रोस्टर बिंदु नहीं है।

(29) यह आग्रह करना कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत किया गया था और प्रत्यावर्तन का सवाल नहीं उठता है, पूरी तरह से गलत होगा।अजीत सिंह-2 (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जिन लोगों को गलती से पदोन्नत किया गया था, उनकी वरिष्ठता को पुनः बनाया जाना चाहिए।सुरक्षा केवल तभी उपलब्ध है जब पदोन्नति 1 मार्च, 1996 से पहले की गई हो।अन्यथा, एक बार वरिष्ठता को फिर से तैयार करने के बाद, उन्हें नीचे खिसकना पड़ा।इसे विशेष रूप से अजीत सिंह-2 के मामले में ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार, यह तर्क कि सुबे सिंह बहमनी के मामले (ऊपर) में पक्षों के बीच एक निर्णय है जो उन्हें कुछ लाभ देता है, विफल होना चाहिए।

(30) यह देखने के लिए कि राज्य ने क्या किया है, यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य ने उपाधीक्षक के स्तर तक आवश्यक आरक्षण दिया है।अजीत सिंह-2 के मामले में निर्णय के संदर्भ में, 1 मार्च, 1996 तक पदोन्नत किए गए लोग सुरक्षित हैं और कोई आरक्षण नहीं है।कोई आरक्षण नहीं हो सकता है लेकिन आगे कोई पदोन्नति नहीं है कि वे कल्पना के किसी भी विस्तार से सामान्य उम्मीदवारों पर वरिष्ठता का दावा कर सकते हैं।यदि आरक्षण के सिद्धांत की गलत धारणा से, कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 1 मार्च, 1996 के बाद पदोन्नत किया गया था, तो उन्हें नीचे गिरना पड़ा और उस पद पर वापस आना पड़ा जिसके बारे में वे सुरक्षा चाहते हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि अजीत सिंह-2 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समीक्षा की अनुमति दी थी और आरक्षण के कारण पदोन्नत लोगों को तदर्थ माना था।नतीजतन, वे सभी निजी

उत्तरदाता जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो याचिकाकर्ताओं को उप-अधीक्षक के स्तर पर पकड़ लेंगे, जहां से कोई आरक्षण नहीं है, जैसा कि राज्य द्वारा ध्यान दिया गया है, याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ हो जाएंगे।हमारे यह पूछने पर कि राज्य द्वारा क्या किया गया है, याचिकाकर्ता साधु सिंह के एक चार्ट में वर्णित किया गया था।हम धारावाहिक संख्या 129 गुरु सरूप तक इसके एक हिस्से को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	लिपिक के रूप में नियुक्ति की	सहायक के रूप में पदोन्नति की तिथि	त्वरित वरिष्ठता के आधार परडिप्टी के रूप में रोस्टर पर पदोन्नति/पदोन्नति की वास्तविक	अजीत सिंह-I के अनुसार उप अधीक्षक के रूप में पदोन्नति की मानी गई तिथिमानित	अधीक्षक के रूप में त्वरित वरिष्ठता पर पदोन्नति की वास्तविक तिथि/पदोन्नति	अजीत सिंह-द्वितीय के अनुसार अधीक्षक के रूप में पदोन्नति की मानी गई तिथि	सचिव के तहत त्वरित वरिष्ठता पर पदोन्न	अजीत सिंह-II के अनुसार	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	एन
! को 92	XX	XX	XX		XX		XX		XX	XX
93	साधु	9-8-71	2-6-77	21-3-90	15-2-99	3-4-91	बारी नहीं आई	19-2-	बारी नहीं	31-5-
94	आर डी गुप्ता	7-4-60	15-6-70	30-4-90	24-6-88	3-4-91	26-10-89	19-2-97	18-6-93	31-3-98
95	के एल शर्मा	7-4-60	15-6-70	.8-10-90	24-6-88	सेवानिवृत्त हुए।	-	-	-	31-10-90
96	धरम पॉल	8-9-60	15-6-70	23-11-90	24-6-88	3-4-91	16-3-90	शामिल नहीं	--	31-10-93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	एम. एल. घाइ	17-10-60	16-6-70	23-11-	1-12-	3-4-91	16-3-	19-2-97	18-6-93	31-10-98
98	एस. एन. बत्रा	18-10-60	15-6-70	23-11-	1-12-	8-7-91	16-3-	पदोन्नति नहीं मिली।	--	31-05-96
99	बी. एल. ग्रोवर	12-8-71	28-7-77	23-11-	15-2-	8-7-91	बारी नहीं	19-2-97	बारी नहीं आई	31-3-
10	हरि चंद	27-6-60	15-6-70	7-1-91	1-12-	8-7-91	16-3-	19-2-97	18-8-93	28-2-97
10	के. एल. भंडुला	16-11-60	18-6-70	7-1-91	1-12-88	29-7-91	16-3-	19-2-97	16-11-	30-6-97
10	आतम लाल	12-12-60	17-6-70	7-1-91	1-12-88	29-7-91	26-9-	19-2-97	16-11-	30-4-98
10	हरि चंद हुड्डा	6-1-61	18-6-70	7-1-91	1-12-88	29-7-91	26-9-	पदोन्नति नहीं मिली।		'30-6-
10 4	.शमशेर सिंह (ईसा पूर्व)	17-11-60	17-6-70	7-1-91	1-12-88	■29-7-91 '	24-10-90	पदोन्नति नहीं मिली।		31-7-94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	भरत सिंह (ईसा पूर्व)	8-71	14-10-77	7-1-91	अभी भी	29-7-91	बारी नहीं	16-10-98	बारी नहीं आई	31-8-2006
10	ओ पी शर्मा	13-2-61	17-6-70	22-2-91	6-1-98	29-7-91	14-11-	19-2-97	24-3-94	31-10-
10	सोमा देवी	8-3-61	17-6-70	22-2-91	23-6-	29-7-91	14-11-	पदोन्नति		31-8-94
10	बावा सिंह	9-2-59	8-8-70	22-4-91	8-8-98	18-9-91	14-11-	<9-2-97	24-3-94	31-5-99
10	लेहना सिंह	20-4-61	1-7-70	22-4-91	31-10-	18-9-91	27-12-	19-2-97	24-3-94	31-8-97
11	के. एस.	1-6-63	21-8-70	22-4-91	31-10-	18-9-91	27-12-	पदोन्नति		30-6-96
11	आर डी एस	25-10-61	27-11-	24-4-91	31-10-	नहीं।				31-10-
112	ए सी कपिल	27-11-61	21-11-70	22-4-91	31-10-98	18-9-91	27-12-90	19-2-97	24-3-94	31-3-2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	बी. आर.	28-11-	23-11-	22-4-91	31-10-	24-10-	8-2-91	19-2-97	26-8-94	30-6-
114	तारा चंद (एससी)	8-71	14-10-77	22-4-91	अभी भी मूल्यांकन किया	24-10-91	बारी नहीं आई	16-10-98	बारी नहीं आई	31-1-2009
115	भू देव शर्मा	30-1-62	15-12-70	8-8-91	31-3-90	24-10-91	8-2-91	पदोन्नति नहीं		31-3-93
11	बृज मोहन	24-6-62	14-1-	8-8-71	31-3-	24-10-	3-4-91	19-2-97	26-8-94	31-10-
11	खुशाल सिंह	24-4-62	14-1-	8-8-91	30-4-	3-1-92	3-4-91	पदोन्न		30-11-
1	पुष्पा भाटिया	26-6-62	14-1-	8-8-91	8-10-	3-1-92	3-4-91	मृत्यु हो	-	मृत्यु हो
1	सरोज बाला	19-9-62	14-1-	8-8-91	23-11-	3-1-92	3-4-91	पदोन्न		31-7-97
12	ईश्वर चंद	21-2-62	31-8-	8-8-91	23-11-	3-1-92	8-7-91	16-9-97	26-8-94	29-2-
12	सुदर्शन गारा	14-12-	1-9-71	8-8-91	23-11-	3-1-92	8-7-91	पदोन्नति नहीं		30-4-96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	शाम सुंदर मेहता	28-6-63	1-9-71	8-8-91	23-11-90	3-1-92	8-7-91	पदोन्नति नहीं		31-1
123	राम प्रकाश	10-8-59	24-9-91	8-8-91	9-10-91	3-1-92	8-7-91	- पदोन्नति	–	30-4
124	ओम प्रकाश रंगा (एससी)	12-8-71	14-10-77	8-8-91	अभी भी मूल्यांक न किया	3-1-92	बारी नहीं आई	शामिल नहीं हुआ		31-7
125	मणि राम	12-8-	14-10-	8-8-91	बारी	4-3-	-करो -	4-12-98	बारी नहीं	30-9
126	राम सरूप	21-8-	24-9-	9-10-	7-1-91	4-3-	29-7-	16-9-97	6-10-94	30-1
127	धनी राम	6-9-63	24-9-	9-10-	7-1-91	4-3-	29-7-	16-9-97	10-2-95	30-4
128	नगीना सिंह	7-9-63	24-9-	9-10-	7-1-91	4-3-	29-7-	13-10-	28-3-95	30-1
129	गुरु सरूप	27-8-	11-10-	9-10-	7-1-91	4-3-	29-7-	13-10-	28-3-95	31-1
130 को 211	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X

(31) प्रार्थियों की पक्ष से यह स्वीकार किया गया है कि वे क्रम संख्या 107 तक प्रार्थी साधू सिंह के साथ बराबर हो जाएंगे, लेकिन दूसरों के संबंध में नहीं।ऊपर कुछ नामों को पुनः प्रस्तुत किया गया है।याचिकाकर्ताओं के तर्क का कोई लाभ नहीं है।अन्य व्यक्ति जो रिट याचिका में निजी प्रतिवादीगण हैं, अनिवार्य रूप से बराबर हो जाएंगे क्योंकि याचिकाकर्ता को गलती से अधीक्षक के रूप में और उसके बाद 19 फरवरी, 1997 को अवर सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है, यानी 1 मार्च, 1996 के बाद।अन्य सभी निजी प्रतिवादीगण को कैच-अप के सिद्धांत के आधार पर उस स्तर तक आना था जहां आरक्षण निर्धारित किया गया था और आवश्यक रूप से वे याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ बन जाएंगे।एकमात्र आशाजनक बात यह होगी कि उन्हें वापस नहीं किया जाएगा क्योंकि वे 1 मार्च, 1996 से पहले अधीक्षक बन गए थे।राज्य द्वारा उत्तर में यह समझाया गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, साधु सिंह याचिकाकर्ता की वरिष्ठता की समीक्षा की गई और वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवारों को स्तर 3 तक पहुंचने पर बार-बार उनसे ऊपर रखा गया।यह बताया गया है कि साधु सिंह याचिकाकर्ता को 3 अप्रैल, 1991 को वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवारों के दावे की अनदेखी करते हुए त्वरित वरिष्ठता के आधार पर अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिन्हें बाद में

स्तर 3 पर पदोन्नत किया गया था।स्तर 4 पर, साधु सिंह याचिकाकर्ता की वरिष्ठता की समीक्षा की गई थी और जब सामान्य उम्मीदवार स्तर 4 पर पहुंचे तो उन्हें फिर से तय किया गया था।उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, उन्हें अधीक्षक के पद से वापस नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन्हें 1 मार्च, 1996 से पहले पदोन्नत किया गया था।याचिकाकर्ता नंबर 2 बी. एल. ग्रोवर की भी यही स्थिति है।नतीजतन, हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

(32) हमारे इस निष्कर्ष को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एमजी. बडप्पनवार और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य**[12], (2000 की सिविल अपील संख्या 6970-6971 1 दिसम्बर, 2000 को निर्णय लिया गया) मामले में दिए गए निर्णय से मजबूती मिलती है। ।इसमें भी विवाद एक जैसा ही था।कर्नाटक राज्य में कार्यकारी अभियंता के स्तर तक आरक्षण था।रोस्टर पदोन्नति पर वरिष्ठता को गिनने की अनुमति देने वाला कोई नियम नहीं था।अधीक्षण अभियंता के स्तर तक कोई आरक्षण नहीं था।जाहिर है, कुछ आरक्षित उम्मीदवारों को स्तर 4 यानी अधीक्षण अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था, जो उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से वरिष्ठ मानते थे।उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कियाः–

> "......लेकिन अजीत सिंह द्वितीय में, इस पहलू को स्पष्ट किया गया है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 2 (सी), 4 और 4ए जैसे वरिष्ठता नियम जो प्रारंभिक पदोन्नति की तारीख से वरिष्ठता की गणना करने की अनुमति देते हैं, नियमों के अनुसार की जाने वाली सामान्य पदोन्नति को नियंत्रित करते हैं-मूल स्तर पर वरिष्ठता द्वारा, वरिष्ठता-सह-योग्यता द्वारा या

[12] 2001 एस.सी.T. 2

चयन द्वारा,लेकिन रोस्टर के माध्यम से की गई पदोन्नति के लिए नहीं।यह पदोन्नति केवल सेवा के विभिन्न स्तरों पर पिछड़े वर्गों के उचित प्रतिनिधियों के प्रवेश के सीमित उद्देश्य के लिए आयोजित की गई थी।यदि नियमों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि रोस्टर प्वाइंट पदोन्नतियों को वरिष्ठता प्रदान की जाए-जो सामान्य माध्यम से नहीं गए हैं जहां बुनियादी वरिष्ठता या चयन प्रक्रिया शामिल है-तो नियम, जो आयोजित किए गए थे, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के विपरीत होंगे।अनुच्छेद 16 (4ए) भी मदद नहीं कर सकता है।अगर इस तरह की वरिष्ठता दी जाती है, तो यह असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने के बराबर होगा।"

इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः–

"इसलिए, यह स्पष्ट है कि अजीत सिंह द्वितीय के अनुसार, कार्यकारी अभियंताओं की श्रेणी में वरिष्ठता सूचियों की पहले समीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें सामान्य उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों की तुलना में वरिष्ठ माना जाए, बशर्ते वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार संबंधित आरक्षित उम्मीदवार को अधीक्षण अभियंता के रूप में पदोन्नत करने से पहले स्तर 3 (कार्यकारी अभियंता) तक पहुंच जाएं।वरिष्ठता की समीक्षा करने और कार्यकारी अभियंता के स्तर पर इसे फिर से तय करने के बाद, अधीक्षण अभियंता की श्रेणी में पदोन्नति की अगली समीक्षा की जानी है।स्तर I (कनिष्ठ अभियंता जिसे बाद में सहायक अभियंता के रूप में बुलाया गया) और स्तर 2 (सहायक कार्यकारी अभियंता) में आरक्षित उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार करते समय, आर. के. सभरवाल के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसा कि अजीत सिंह II में समझाया गया है। अधीक्षण अभियंता स्तर पर पदोन्नति की समीक्षा के बाद, मुख्य अभियंता या समकक्ष पदों या उच्चतर पदों पर आगे की पदोन्नति को भी संशोधित किया जाना है।"

(33) दूसरे शब्दों में, जैसा कि तत्कालीन वर्तमान विवाद में था, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया और कहा कि अजीत सिंह-II. के मामले में निर्णय के अनुसार, वरिष्ठता सूची को उस स्तर तक तैयार किया जाना चाहिए जहां आरक्षण की अनुमति है।उक्त वरिष्ठता सूची की समीक्षा करने और उस स्तर पर इसे फिर से तय करने के बाद, अधीक्षण अभियंता के अगले स्तर पर पदोन्नति की समीक्षा की जानी चाहिए।बेशक, 1 मार्च, 1996 से पहले पदोन्नत किए गए लोगों को वापस लेने की अनुमति नहीं थी।वर्तमान विवाद में ठीक यही किया गया है। अजीत सिंह और आरके सब्बरवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की वरिष्ठता बहाल कर दी गई है और उन्हें प्रभावी तिथि से पदोन्नत किया जा रहा है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, दुर्भाग्य से, कुछ आरक्षित उम्मीदवारों को वापस करना पडेगा ।

(34) इन कारणों से, हम यह मानते हैं कि दोनों रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है और इन्हें कोई लागत के आदेश के बिना खारिज किया जाता है।

आर.एन.आर

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और न्यायमूर्ति आर. सी. कथुरिया के समक्ष

झरमल,- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी. 2000 की संख्या 6335

8 मार्च, 2001

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994- धारा 175 (1) *(क्यू)- भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 14* & *226–पंच के पद के लिए चुनाव-धारा 75 (1)* (क्यू) *में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, वह पंच का पद धारण करने के लिए पात्र नहीं है-चाहे वह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता हो- फैसला किया, नहीं।*

यह माना गया कि 1994 के अधिनियम की धारा 175 (1) (क्यू) के अवलोकन से पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं (दो से अधिक बच्चे कहने के लिए 1995 में प्रावधान में संशोधन किया गया है) वह ग्राम सरपंच का पद धारण करने के योग्य नहीं है।यह प्रावधान याचिकाकर्ता को बच्चे पैदा करने से नहीं रोकता है।यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता है।इसमें केवल यह प्रावधान है कि याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति को सरपंच का पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों को संदेश देना है।जो लोग गाँवों में लोगों का नेतृत्व करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें एक व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित करना चाहिए।इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विधानमंडल ने प्रावधान किया है कि दो से अधिक जीवित बच्चों वाला व्यक्ति सरपंच का पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।विवादित प्रावधान किसी भी कानूनी दोष से ग्रस्त नहीं है।

(पैरास 6 &8)

सतीश चौधरी, अधिवक्ता-याचिकाकर्ता की ओर से

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा